गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 056
दि. 25.06.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

कच्चे तेल में बड़ी गिरावट, लेकिन पेट्रोल-डीजल सस्ता होने का इंतजार अभी बाकी; वैश्विक बाजार में बदले समीकरण

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट ने एक बार फिर उम्मीद जगाई है कि आने वाले समय में आम लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की दिशा में प्रगति तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लौटती दिखाई दे रही है। इसका असर सीधे तौर पर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है, जो अब लगभग चार महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिलने की संभावना कम है और इसके लिए अभी कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है।

पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया में बढ़े भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया था। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव तथा होर्मुज जलमार्ग पर संभावित संकट की आशंकाओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। उस समय कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने तेल की कीमतों के 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका जताई थी और बाजार में भारी अनिश्चितता का माहौल बन गया था। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। तनाव कम होने और आपूर्ति मार्गों के सुरक्षित होने से वैश्विक बाजार में भरोसा लौटा है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतें गिरकर लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में शांति बनी रहती है और आपूर्ति श्रृंखला में कोई नया व्यवधान नहीं आता, तो कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का यह दौर कुछ और समय तक जारी रह सकता है। इससे तेल आयात करने वाले देशों को राहत मिलेगी और उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल के माध्यम से पूरा करता है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई इस गिरावट का सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं तक तुरंत पहुंचने की संभावना नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार की मौजूदा दरों के आधार पर तय नहीं होतीं, बल्कि इसके पीछे कई आर्थिक और नीतिगत कारक काम करते हैं। तेल कंपनियां आमतौर पर एक से डेढ़ महीने पहले ही कच्चे तेल की खरीद के लिए समझौते कर लेती हैं। ऐसे में वर्तमान में सस्ते हुए तेल का प्रभाव तब दिखाई देगा जब पहले से खरीदे गए महंगे तेल का स्टॉक समाप्त हो जाएगा।

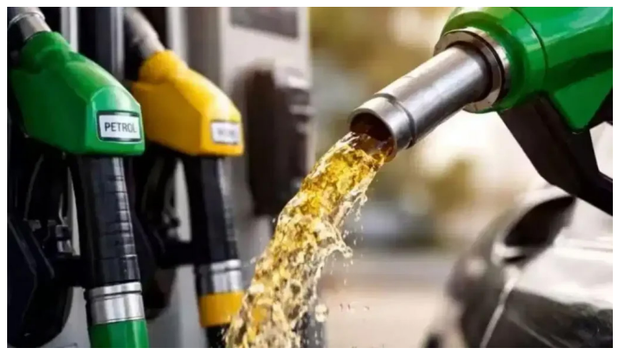

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ समय में तेल विपणन कंपनियों को कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण भारी वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा है। अनुमान है कि संकट के दौर में कंपनियों को प्रतिदिन सैकड़ों करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने पर कंपनियां पहले अपने वित्तीय घाटे की भरपाई करने की कोशिश करेंगी। यही कारण है कि खुदरा कीमतों में तुरंत कटौती की संभावना सीमित मानी जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार की कर नीति भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रभावित करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक नीचे बनी रहती हैं, तो सरकार पहले अपने राजस्व संतुलन को ध्यान में रखते हुए उत्पाद शुल्क संबंधी निर्णय ले सकती है। अतीत में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटने के बावजूद खुदरा स्तर पर राहत धीरे-धीरे दी गई। इस बीच ऊर्जा बाजार में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम ने ध्यान आकर्षित किया है। अमेरिका से मिली संभावित राहत और प्रतिबंधों में नरमी के संकेतों के बाद ईरान ने भारतीय तेल कंपनियों से दोबारा संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इससे भारत और ईरान के बीच कच्चे तेल के व्यापार के पुनर्जीवित होने की संभावना बढ़ गई है। यदि ऐसा होता है तो भारत को अपेक्षाकृत सस्ता कच्चा तेल उपलब्ध हो सकता है, जिससे भविष्य में आयात लागत कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ईरानी तेल की वापसी का लाभ भी तत्काल नहीं मिलेगा। भारतीय रिफाइनरियों ने पहले ही आने वाले कई सप्ताहों और महीनों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल खरीद रखा है। इसलिए नए समझौतों के प्रभाव को घरेलू बाजार तक पहुंचने में कम से कम पांच से छह महीने का समय लग सकता है। इसके बावजूद ऊर्जा क्षेत्र में इसे एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

भारत और ईरान के बीच ऊर्जा संबंधों का इतिहास काफी पुराना रहा है। एक समय ईरान भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल था। लेकिन वर्ष 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत को ईरान से तेल आयात रोकना पड़ा था। अब यदि परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं तो दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार फिर से शुरू हो सकता है, जिसका लाभ भारत की अर्थव्यवस्था को मिल सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरानी तेल भारत के लिए कई दृष्टियों से लाभकारी साबित हो सकता है। सबसे पहले, ईरान प्रतिस्पर्धी दरों पर तेल उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। माना जा रहा है कि बाजार में अपनी हिस्सेदारी दोबारा मजबूत करने के लिए वह भारत को आकर्षक छूट भी दे सकता है। यदि ऐसा होता है तो भारत को रूस के बाद एक और बड़ा सस्ता आपूर्तिकर्ता मिल जाएगा।

इसके अतिरिक्त भारत का तेल आयात बिल भी उल्लेखनीय रूप से कम हो सकता है। विश्लेषकों के अनुसार यदि भारत पूर्व की तरह बड़ी मात्रा में ईरानी तेल खरीदता है और उस पर प्रति बैरल कुछ डॉलर की छूट मिलती है, तो सालाना हजारों करोड़ रुपये की बचत संभव हो सकती है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। परिवहन के दृष्टिकोण से भी ईरानी तेल भारत के लिए लाभदायक माना जाता है। रूस और अमेरिका से कच्चा तेल भारत तक पहुंचने में कई सप्ताह लग जाते हैं, जबकि ईरान की भौगोलिक निकटता के कारण वहां से तेल कुछ ही दिनों में भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच सकता है।

एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर मिजोरम सीएम का विराम, बोले-गठबंधन नहीं, सहयोग जारी रहेगा

आइजोल। मिजोरम की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री Lalduhoma ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल होने की अटकलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) का कभी भी एनडीए में शामिल होने का एजेंडा नहीं रहा और न ही भविष्य में ऐसी कोई योजना है। उनके इस बयान ने उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि मिजोरम की सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय राजनीति के बड़े गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार के साथ टकराव की बजाय सहयोगपूर्ण संबंधों में विश्वास रखती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह किसी राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ZPM एक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति है, जो मिजोरम की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और आगे भी इसी दिशा में कार्य करती रहेगी।

राजनीतिक हलकों में पिछले कुछ समय से यह चर्चा तेज थी कि मिजोरम की सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। इन अटकलों को तब और बल मिला जब केंद्र सरकार के कुछ शीर्ष नेताओं द्वारा क्षेत्रीय दलों के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाने की बात सामने आई। हालांकि, मुख्यमंत्री ने इन सभी चर्चाओं को सिरे से खारिज करते हुए स्थिति को स्पष्ट कर दिया।

लालदुहोमा ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की ओर से उनकी पार्टी को एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण कई बार दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने समय-समय पर ZPM को राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन पार्टी ने हर बार यह निर्णय लिया कि वह औपचारिक गठबंधन का हिस्सा बने बिना भी केंद्र के साथ बेहतर समन्वय बनाए रख सकती है। मुख्यमंत्री के अनुसार, उनकी प्राथमिकता मिजोरम के विकास और राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनने से पहले यह देखना आवश्यक होता है कि उससे राज्य के स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ZPM इस संतुलन को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए उसने स्वतंत्र राजनीतिक राह को ही चुना है। विश्लेषकों का मानना है कि मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्य में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहां की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियां देश के अन्य हिस्सों से काफी भिन्न हैं। ऐसे में क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखना कई दलों के लिए प्राथमिकता होती है। ZPM का यह रुख इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वह राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग तो बनाए रखना चाहती है, लेकिन अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं करना चाहती। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंध बनाए रखना किसी भी सरकार के लिए जरूरी होता है, विशेषकर तब जब राज्य विकास परियोजनाओं, वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए केंद्र पर निर्भर हो। ऐसे में ZPM का यह संतुलित दृष्टिकोण उसे व्यावहारिक राजनीति की दिशा में आगे बढ़ाता है। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने अपने बयान में यह भी संकेत दिया कि उनकी सरकार केंद्र के साथ संवाद और सहयोग को प्राथमिकता देती रहेगी, लेकिन किसी भी राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनने की आवश्यकता नहीं समझती। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का फोकस शासन, विकास और जनता की भलाई पर केंद्रित रहेगा। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल मिजोरम की सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय राजनीति के किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने के मूड में नहीं है। हालांकि, केंद्र और राज्य के बीच सहयोगात्मक संबंध भविष्य में भी जारी रहेंगे। इस घटनाक्रम ने पूर्वोत्तर की राजनीति में एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या क्षेत्रीय दलों के लिए राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होना लाभकारी है या स्वतंत्र रहकर केंद्र के साथ सहयोग बनाए रखना अधिक व्यावहारिक विकल्प है।

विदेश यात्रा पर तत्काल राहत नहीं, अभिषेक बनर्जी की जल्द सुनवाई की मांग हाईकोर्ट ने ठुकराई

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से उस समय आंशिक झटका लगा, जब अदालत ने उनकी याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। हालांकि उनकी विदेश यात्रा की अनुमति से जुड़ी मुख्य याचिका स्वीकार कर ली गई है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि मामले की सुनवाई किसी विशेष प्राथमिकता के आधार पर नहीं होगी और इसे सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही सुना जाएगा। हाईकोर्ट के इस रुख ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज कर दी है, क्योंकि मामला न केवल एक जनप्रतिनिधि की विदेश यात्रा से जुड़ा है, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहे एक संवेदनशील विवाद से भी संबंधित है।

मंगलवार को अभिषेक बनर्जी ने अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह याचिका न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। याचिका के साथ ही उनके वकीलों की ओर से अदालत से अनुरोध किया गया था कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए मामले की तत्काल सुनवाई की जाए, ताकि विदेश यात्रा में किसी प्रकार की देरी न हो। लेकिन बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मामले में तत्काल सुनवाई का कोई विशेष आधार नहीं बनता है। अदालत ने कहा कि याचिका पर विचार अवश्य किया जाएगा, लेकिन उसे सामान्य सूची और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही सुना जाएगा। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने त्वरित सुनवाई की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने मुख्य याचिका को रिकॉर्ड पर स्वीकार करते हुए आगे की सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा है।

यह मामला हाल ही में सामने आए उस विवाद से जुड़ा हुआ है जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा से संबंधित कुछ दस्तावेजों पर विधायकों के हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठाए गए थे। आरोप है कि विपक्ष के लिए आरक्षित कुछ महत्वपूर्ण पदों और समितियों से जुड़े प्रस्तावों पर जिन विधायकों के हस्ताक्षर दर्ज किए गए, उनमें कुछ हस्ताक्षरों के मेल नहीं खाने की शिकायत सामने आई थी। इसी शिकायत के आधार पर जांच शुरू हुई और मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने अभिषेक बनर्जी से दो बार पूछताछ की थी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि संबंधित दस्तावेजों में हस्ताक्षरों को लेकर उठे विवाद में उनकी कोई भूमिका है या नहीं। हालांकि अभिषेक बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार इन आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बताते रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अभिषेक बनर्जी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट की एक अन्य एकल पीठ ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की थी। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की पीठ ने उन्हें पुलिस की कठोर कार्रवाई से अस्थायी सुरक्षा देते हुए कुछ शर्तें भी निर्धारित की थीं। उन्हीं शर्तों में एक महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि अभिषेक बनर्जी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। यही कारण है कि आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने से पहले उन्हें फिर से हाईकोर्ट की अनुमति लेना आवश्यक हो गया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह निर्णय प्रक्रिया संबंधी दृष्टिकोण को दर्शाता है। अदालत ने यह संकेत दिया है कि किसी भी याचिकाकर्ता को केवल इसलिए विशेष प्राथमिकता नहीं दी जा सकती क्योंकि वह सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्ति है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया सभी के लिए समान है और मामलों की सुनवाई तय नियमों और परिस्थितियों के आधार पर ही होगी।

राजनीतिक दृष्टि से भी इस मामले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकारों में गिने जाते हैं और पार्टी संगठन में उनकी भूमिका बेहद प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसे में उनसे जुड़े किसी भी कानूनी घटनाक्रम पर राजनीतिक दलों और मीडिया की नजर बनी रहती है। विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठाता रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताती रही है।

दिल्ली से अमृतसर जा रही एअर इंडिया फ्लाइट पाक हवाई क्षेत्र में पहुंची, DGCA ने शुरू की जांच

नई दिल्ली। दिल्ली से अमृतसर जा रही एअर इंडिया की एक उड़ान के दौरान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में सीमित समय के लिए प्रवेश का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए नागरिक उड्डयन नियामक प्राधिकरण (DGCA) और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। विमानन सुरक्षा से जुड़े इस मामले ने एक बार फिर क्षेत्रीय हवाई संचालन और उड़ान प्रबंधन प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

यह घटना 22 जून की बताई जा रही है, जब एअर इंडिया की उड़ान संख्या AI-479 दिल्ली से अमृतसर के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के सामान्य संचालन के दौरान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन किसी तकनीकी या परिचालन कारण के चलते विमान को "गो-अराउंड" प्रक्रिया अपनानी पड़ी। इसी दौरान विमान कुछ समय के लिए नियंत्रण क्षेत्र से बाहर जाकर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया।

एअर इंडिया ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि उड़ान सुरक्षित रूप से संचालित की जा रही थी और यात्रियों की सुरक्षा को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं हुआ। एयरलाइन के अनुसार, अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के प्रयास के दौरान जब विमान को दोबारा ऊंचाई लेने के लिए निर्देशित किया गया, उसी प्रक्रिया में यह असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह एक तकनीकी और नेविगेशनल प्रक्रिया के दौरान हुआ सीमित समय का प्रवेश था।

एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि गो-अराउंड प्रक्रिया विमानन संचालन का एक सामान्य हिस्सा होती है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब लैंडिंग सुरक्षित रूप से संभव नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में पायलट विमान को पुनः ऊंचाई पर ले जाकर दोबारा लैंडिंग का प्रयास करते हैं। हालांकि इस दौरान मार्ग और हवाई क्षेत्र का सटीक पालन बेहद महत्वपूर्ण होता है, और इसी क्रम में यह घटना सामने आई। Air India ने कहा कि इस मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है और सभी संबंधित रिपोर्ट्स को नियामक एजेंसियों को सौंप दिया गया है। एयरलाइन ने यह भी आश्वासन दिया है कि सुरक्षा मानकों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

इस घटना को इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र पहले से ही प्रतिबंधित कर रखा है। सीमा तनाव और सुरक्षा कारणों के चलते दोनों देशों के बीच हवाई मार्गों पर पहले से ही कई प्रकार की सीमाएं लागू हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का हवाई क्षेत्र उल्लंघन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील मुद्दा बन सकता है।

विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि गो-अराउंड जैसी प्रक्रिया के दौरान पायलट को अत्यंत सटीक नेविगेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के निर्देशों का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार की देरी या निर्देशों में मामूली चूक भी विमान को निर्धारित हवाई क्षेत्र से बाहर ले जा सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में अक्सर तकनीकी और परिचालन कारणों का मिश्रण जिम्मेदार होता है, और अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आता है।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, आधुनिक विमान GPS और रडार सिस्टम से पूरी तरह लैस होते हैं, लेकिन व्यस्त हवाई मार्गों और आपातकालीन प्रक्रियाओं के दौरान मानव और तकनीकी समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि इस घटना की विस्तृत जांच आवश्यक मानी जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, घटना के बाद संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स से भी रिपोर्ट मांगी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गो-अराउंड के दौरान विमान को किस तरह के निर्देश दिए गए थे और किस स्तर पर मार्ग विचलन हुआ।

संपादकीय

सुखपुरी के सुख-दुख

आज स्मार्टफोन के बच्चों व किशोरों पर पड़ने वाले घातक प्रभावों से पूरी वैश्विक बिरादरी फिक्रमंद है। लाइलाज मर्ज बनती इस लत के खिलाफ परंपरागत समाजों व विकासशील देश ही नहीं, बल्कि आस्ट्रेलिया, फ्रांस,ब्रिटेन आदि विकसित देशों में भी एक उम्र के बाद ही स्मार्ट फोन के इस्तेमाल करने के लिए कानून बन रहे हैं। सोशल मीडिया के जनक अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ अदालतों में मोटे मुआवजे वसूले गए हैं। इसी बीच हरियाणा के नूंह जिले के सुखपुरी गांव में एक अभिनव पहल हुई है। यूं तो स्मार्टफोन आज आवश्यक बुराई बनते जा रहे हैं, लेकिन सुखपुरी के दुख अलग हैं। गांव की पहचान साइबर क्राइम के हब के रूप में होने लगी है। आये दिन गांव में पुलिस की दस्तक से उन्हें बदनामी महसूस होती है। उनका कहना है कि इस गांव के कुछ युवाओं के साइबर क्राइम में शामिल होने के आरोपों के चलते बाहरी ग्रामीण गांव में रिश्ते करने से कतरा रहे हैं। गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सामने 55 मोबाइल हैंडसेट पटककर तोड़ दिए। उनका मकसद गांव को साइबर क्राइम हब के दाग से मुक्त कराना था। ग्रामीणों ने जरूरत के लिये बेसिक फोन इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। बताते हैं कि नूंह क्षेत्र के 57 गांवों के लोगों ने भी ऐसी पहल करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी में बड़े-बुजुर्गों के फैसले के खिलाफ गुस्सा है। उनका मानना है कि इस फैसले से उनकी आर्थिक प्रगति बाधित होगी। कई लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर निर्भर है। उनकी दलील है कि महज कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी पीढ़ी को नहीं दी जा सकती। वे ऑनलाइन पढ़ाई व स्कॉलरशिप पोर्टल से कट जाएंगे। वहीं यूपीआई पेमेंट समेत ऑनलाइन भुगतान के तौर-तरीके बाधित होंगे। लेकिन सुखपुरी के लोगों के गांव का नाम साइबर क्राइम से जुड़ने के दुख को भी समझने की जरूरत है।

सही मायने में आज जरूरत एक बीच का रास्ता तलाशने की है। ताकि साइबर क्राइम में युवाओं के लिप्त होने से गांव की बदनामी भी न हो, और डिजिटल गतिविधियां भी चलती रहें। निस्संदेह, तकनीक को धोखा देने और गैर-कानूनी फायदा उठाने का जरिया नहीं बनने दिया जाना चाहिए। नियामक एजेंसियों को सामुदायिक नेताओं की मदद से ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए, जो अक्सर साइब्रर फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन स्कैम में लिप्त रहते हैं। वाकई आज स्मॉर्ट फोन दुधारी तलवार बन गए हैं। ऐसा जिन्न, जिसमें अच्छाई भी है और बुराई भी। जिसकी वजह से तुरंत पैसा कमाने के फेर में युवा साइबर अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। सवाल केवल साइबर अपराधों का ही नहीं है, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्मों में अश्लील सामग्री का बोलबाला है। जिससे किशोर व युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं। कई तरह की भाषाई विकृतियां सामने आ रही हैं। समय व पैसा बचाने के लिये शादियों के कार्ड व्हाट्स ऐप के जरिये भेजने का प्रचलन तो बढ़ा है, लेकिन इससे विवाह समारोह के आमंत्रण की गरिमा व प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। ये स्पष्ट है कि आज स्मॉर्ट फोन सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये शिक्षा, बैंकिंग,सरकारी सेवाओं, रोजगार के मौके तलाशने व वीडियो कॉलिंग का जरिया भी हैं। ऐसे समय में, जब गांवों में सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिये डिजिटल कनेक्टिविटी अपरिहार्य है, स्मार्टफोनों के उपयोग से युवाओं को पूरी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता। डिजिटल दौर में उन युवाओं के भी अलग-थलग पड़ने की आशंकाएं हैं, जिनका भविष्य बचाने के लिये यह पहल की जा रही है। दरअसल, मुद्दा स्मॉर्ट फोन डिवाइस का नहीं है, बल्कि इसके गलत इस्तेमाल का है। जिसे समाज में बढ़ती बेरोजगारी, कौशल की कमी और रातों-रात अमीर बनने की चाह बढ़ावा देती है। ऐसे कृत्यों के कानूनी नतीजों से युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है। इस संकट के मूल को तलाशकर, उसका उपचार करना जरूरी है। आवश्यकता डिजिटल दुनिया से कटने की नहीं, बल्कि साइबर साक्षरता व डिजिटल जिम्मेदारी को बढ़ावा देने की है। बहरहाल, सुखपुरी की सामूहिक कार्रवाई और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए।

संपूर्ण दवा सुरक्षा श्रृंखला को कीजिए मजबूत

“ अधिकारियों को इस गलतफहमी से बचना चाहिए कि सिर्फ बिक्री का तौर-तरीका बदलने से सुरक्षा की संपूर्ण श्रृंखला दुरुस्त हो जाएगी। असली काम एक ऐसी दवा प्रणाली बनाना है, जिसमें दवाएं उत्तम गुणवत्ता की हों, परामर्श तार्किक हों, दवा विक्रेता की जिम्मेदारी तय हो, नागरिक जानकारी युक्त हों और नियामक किसी बड़ी घटना के होने से पहले ही कदम उठा लें।

अक्तूबर, 2025 में, मध्य प्रदेश के एक ज़िले में संदूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की ख़बरों ने देश को झकझोर दिया था। अब, जून, 2026 में, भारत सरकार ने कुछ नियम बदले हैं और 'शेड्यूल के' से सभी सिरप को अनुमति सूची से हटा दिया है। 'शेड्यूल के' में गांवों या ऐसी जगहों पर, जहां पर आबादी एक हज़ार से कम है, गैर-फ़ार्मेसी दुकानों पर भी सिरप बिक्री को मंज़ूरी थी। अब पूरे देश में, दवा युक्त सिरप आम दुकानों पर नहीं रखी जा सकती और उनकी बिक्री डॉक्टर की पर्ची पर होना अनिवार्य है।

मध्य प्रदेश की कफ सिरप त्रासदी के बाद जांच हुई और कुछ नियामक पहल हुई। इस घटना की याद ने नीतिगत फ़ैसले को आकार दिया है। हालांकि, इसे मोटे तौर पर कफ सिरप की बिक्री के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य किए जाने के फ़ैसले के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि ज़्यादातर दवा युक्त कफ सिरपों में (हर्बल सिरप को छोड़कर) ऐसे तत्व होते हैं, जिनकी खरीद या बेचने से पहले डॉक्टर की पर्ची की अनिवार्यता हमेशा से थी। मगर, पालन नहीं किया जाता था।

यह नीतिगत फ़ैसला स्पष्ट रूप से पर्ची की अनिवार्यता को सुदृढ़ करता है। सभी सिरपों में, भारत में सबसे अधिक गलत इस्तेमाल कफ़ सिरप का होता है। कई लोग बीमारी की सही शिनाख्त करवाए बिना खुद से इन्हें खरीद लेते हैं, छूत से लगी सर्दी-खांसी में इनका इस्तेमाल करते हैं जबकि इनसे फायदा बहुत कम होता है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बावजूद यह छोटे बच्चों को बार-बार खुराक दी जाती है। धारणा बना ली कि मीठा तरल नुकसानदायक प्रतीत नहीं होता। कुछ सिरप फार्मूलों में एंटीहिस्टामाइन, डिकंजेस्टेंट, सिडेटिव, ओपिओइड या अल्कोहल जैसे तत्व होते हैं, जो फ़ायदे के बजाय नुकसान अधिक पहुंचा सकते हैं। किशोरों और वयस्कों में भी कुछ किस्म के सिरप का गलत इस्तेमाल होता है। पर्ची की अनिवार्यता बनने से लोग आसानी से इन्हें नहीं खरीद पाएंगे, पहले डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाएगा।

फिर भी, यह कहानी का सिर्फ़ एक हिस्सा है। कई परेशान माता-पिता के लिए बच्चे की खांसी चिंताजनक हो जाती है, और डॉक्टर के पास जाने पर अगर सिरप न लिखा जाए तो उन्हें अक्सर लगता है कि इलाज अधूरा रह गया। मरीज़ अक्सर कफ सिरप लिखने की मांग करते हैं और अगर डॉक्टर मना कर दे, तो कुछ परिवार किसी दूसरे डॉक्टर का रुख करते हैं, जो इसे लिख दे। पुरानी पर्चियों को भी संभालकर रखा जाता है और मिलते-जुलते लक्षणों के लिए वही दवा दोबारा खरीदने में इस्तेमाल किये जाते हैं। ऐसे हालात में, नियमों में यह बदलाव गलत इस्तेमाल को कम कर सकता है, पर्ची की अनिवार्यता होने को मजबूत करता है और गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले व्यवहार को बदल सकता है। बेशक, यह बदलाव स्वागतयोग्य है, लेकिन काफ़ी नहीं है। मध्य प्रदेश की कफ सिरप त्रासदी मुख्य रूप से डॉक्टर की पर्ची न होने के कारण नहीं हुई थी। यह बच्चों तक संदूषित उत्पाद पहुंचने के कारण हुई। जब डायथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल—वे औद्योगिक रसायन, जो दवाओं में कदापि नहीं होने चाहिए—किसी सिरप में मिला दिए जाएँ, तो यह व्यवस्था-तंत्र की विफलता है, जिसकी ज़िम्मेदारी ऊपर स्तर पर बैठे नियामकों की है। इसमें कच्चे माल की खरीद, परीक्षण, लाइसेंसिंग, निरीक्षण और बाज़ार से उत्पाद हटाने जैसी प्रक्रियाओं की प्रभावी निगरानी आवश्यक होती है। डॉक्टर की परामर्श पर्ची उपयोग को तो नियंत्रित कर सकती है, लेकिन संदूषित खेप को सुरक्षित नहीं बना सकती।

अन्य देश इस बाबत उपयोगी सबक हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, खांसी और जुकाम की कुछ दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के उपलब्ध हैं, लेकिन नियामक दो साल से कम उम्र के बच्चों में इनके उपयोग पर चेतावनी देते हैं, और निर्माता आमतौर पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयोग के खिलाफ लेबल पर लिखा होता है। यूनाइटेड किंगडम में, कई खांसी और जुकाम की दवाएं छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं हैं, जबकि छह से बारह वर्ष की आयु के बच्चों में उनका उपयोग स्वास्थ्य कर्मी की देख-रेख में होता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी छोटे बच्चों में इसके उपयोग को हतोत्साहित किया है और लेबल पर बाकायदा चेतावनी छापने को कड़ा कर रखा है। ये देश दुर्घटना अवसर घटाने के लिए केवल डॉक्टर की पर्ची पर निर्भर नहीं हैं। वे आयु प्रतिबंध, चेतावनी लेबल, डाक्टरी परामर्श, विष नियंत्रण प्रणाली, प्रतिकूल घटना पर त्वरित सूचना और निगरानी उपायों का उपयोग करते हैं।

भारत को एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और जुकाम की दवाइयां न तो लिखी जानी चाहिए और न ही दी जानी चाहिए, सिवाय कुछ दुर्लभ मामलों में विशेषज्ञ की सलाह पर। इनसे बड़े बच्चों के लिए, मानकीकृत देखभाल की शुरुआत, दिलासा देने, तरल पदार्थ देकर, जरूरत पड़ने पर बुखार नियंत्रण, सेलाइन ड्रॉप्स, एक साल की उम्र के बाद शहद देना और स्पष्ट चेतावनी संकेतों को बूझना, जिन्हें चिकित्सकीय ध्यान की आवश्यकता है, जैसे उपायों से हो सकती है। माता-पिता को यह पता होना चाहिए कि ज्यादातर खांसी एक संक्रमण रोग है, अपने आप ठीक हो जाती है और इसके लिए सिरप की जरूरत नहीं होती।

दूसरा, उत्पादन नियमों को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। प्रत्येक पी जाने वाली दवा, जिसमें ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या सॉर्बिटोल जैसे सहायक पदार्थ शामिल होते हैं, उनकी विषाक्तता की अनिवार्य जांच की जानी चाहिए। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता लाइसेंस धारक हों, और उन पर नजर रखी जानी चाहिए। राज्य औषधि नियामकों को प्रशिक्षित निरीक्षकों, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल रिकॉर्ड और दबाव से मुक्ति की आवश्यकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर केवल अस्थायी निलंबन ही नहीं, बल्कि मुकदमा और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी होनी चाहिए।

तीसरा, विषाक्ता का पता लगने पर शेष दवा को बाज़ार से तुरंत हटाने वाली प्रणाली होना जरूरी है। एक बार दूषित उत्पाद का संदेह होने पर, सूचना दिनों की बजाय घंटों में प्रसारित होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय डिजिटल दवा रिकॉल प्लेटफॉर्म हो, जोकि बैच नंबर, फार्मेसियों, डॉक्टरों, अस्पतालों और आम जनता से जुड़ा हो, इससे कई जानें बच सकती हैं। हर बोतल पर एक क्यूआर कोड होना चाहिए जिसके माध्यम से माता-पिता निर्माता, बैच नंबर, समाप्ति तिथि और रिकॉल की स्थिति की पुष्टि कर सकें।

चौथा, डॉक्टरों और दवा विक्रेताओं को अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा। परामर्श पर्ची में बीमारी की शिनाख्त, उम्र के हिसाब से दवा की मात्रा और कितने समय तक दवा देनी है, यह सब दर्ज हो। खांसी की मिश्रित दवाएं (कॉम्बिनेशन सिरप) का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे नहीं करना चाहिए। दवा विक्रेताओं को बिक्री का रिकॉर्ड रखना चाहिए, तीमारदारों को जानकारी युक्त करना और असुरक्षित मांगों को साफ इंकार कर देना चाहिए। व्यावसायिक संस्थाओं को चाहिए कि आसानी से समझ आने वाली और व्यावहारिक दिशा-निर्देश जारी करें, जिनका पालन व्यस्त क्लीनिक और फार्मेसियों में किया जाना है।

आखिर में, समुदायों को भागीदार के तौर पर लिया जाना ज़रूरी है। आंगनवाड़ी कर्मी, 'आशा' कर्मी, स्कूल अध्यापक, बच्चों के डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर और लोकल मीडिया तीन आसान बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं : छोटे बच्चों को खुद से तय करके दवा न दें; पुरानी सिरप पर्ची का दोबारा इस्तेमाल न करें। अगर किसी दवा सेवन के बाद बच्चे को पेशाब कम आए, लगातार उल्टी हो, सुस्ती छाए, सांस तेज़ चले या बीमारी और बढ़ जाए, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। पंचायतें और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 'सुरक्षित दवा दिवस' मना सकते हैं, जिनमें परिवार दवाइयों को सुरक्षित तरीके से जांचना, रखना और फेंकना सीख सकें।

अधिकारियों को इस गलतफहमी से बचना चाहिए कि सिर्फ़ बिक्री का तौर-तरीका बदलने से सुरक्षा की संपूर्ण श्रृंखला दुरुस्त हो जाएगी। असली काम एक ऐसा दवा प्रणाली बनाना है जिसमें दवाएं उत्तम गुणवत्ता की हों, परामर्श तार्किक हों, दवा विक्रेता की ज़िम्मेदारी तय हो, नागरिक जानकारी युक्त हों और नियामक किसी बड़ी घटना के होने से पहले ही कदम उठा लें। सवाल यह भी है कि क्या भारत घटना-आधारित उपाय करने से हटकर रोज़मर्रा की दवा-सुरक्षा की ओर बढ़ सकता है।

प्रेरणा

रोटी परोसने का तरीका भी बदल सकता है घर का माहौल!

भारतीय संस्कृति में भोजन का स्थान केवल शरीर की आवश्यकता तक सीमित नहीं है। यहां भोजन को जीवन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक संतुलन का आधार माना गया है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने अन्न को ईश्वर का स्वरूप मानकर उसका सम्मान करने की परंपरा विकसित की। यही कारण है कि भारतीय परिवारों में भोजन बनाने, खाने और परोसने से जुड़े अनेक नियम और मान्यताएं आज भी प्रचलित हैं। इनमें से एक रोचक मान्यता यह है कि रोटी या भोजन को हमेशा सही तरीके से परोसना चाहिए और विशेष रूप से केवल बाएं हाथ से भोजन परोसने से बचना चाहिए। घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर इस बात पर जोर देते हैं और इसे अच्छे संस्कारों का हिस्सा मानते हैं।

जब हम भारतीय जीवनशैली को करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि यहां भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाला माध्यम भी है। परिवार के सभी सदस्य जब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो वह केवल खाने का समय नहीं होता, बल्कि संवाद, प्रेम और अपनत्व का अवसर भी बन जाता है। ऐसे में भोजन परोसने का तरीका भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वह व्यक्ति के संस्कार, व्यवहार और सम्मान की भावना को दर्शाता है। प्राचीन भारतीय परंपराओं में दाहिने हाथ को शुभ और पवित्र कार्यों के लिए उपयुक्त माना गया है। पूजा-पाठ, यज्ञ, दान, तिलक और प्रसाद वितरण जैसे धार्मिक कार्यों में दाहिने हाथ का उपयोग करने की परंपरा आज भी देखने को मिलती है। इसी क्रम में भोजन परोसने के लिए भी दाहिने हाथ को प्राथमिकता दी गई। माना जाता है कि दाहिने हाथ से परोसा गया भोजन सम्मान, सेवा और सकारात्मक भावनाओं का प्रतीक होता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम और आदर के साथ भोजन परोसता है तो सामने वाला व्यक्ति भी उस भाव को अनुभव करता है। भारतीय समाज में भोजन और भावनाओं का गहरा संबंध माना गया है। यह विश्वास है कि भोजन केवल शरीर को ऊर्जा नहीं देता बल्कि मन और विचारों को भी प्रभावित करता है। इसी वजह से भोजन बनाते और परोसते समय मन को शांत और सकारात्मक रखने की सलाह दी जाती है। पुराने समय में माताएं और दादियां भोजन बनाते समय ईश्वर का स्मरण करती थीं और भोजन परोसते समय परिवार के सदस्यों की खुशहाली की कामना करती थीं। उनका मानना था कि शुभ भावनाएं भोजन के माध्यम से पूरे परिवार तक पहुंचती हैं। केवल बाएं हाथ से भोजन परोसने को लेकर जो मान्यताएं प्रचलित हैं, उनके पीछे सामाजिक और व्यवहारिक कारण भी बताए जाते हैं। प्राचीन समय में व्यक्तिगत स्वच्छता के कुछ नियम निर्धारित थे, जिनमें विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग हाथों का उपयोग किया जाता था। इस व्यवस्था के कारण दाहिने हाथ को भोजन और शुभ कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त माना गया। समय के साथ यह व्यवहार परंपरा बन गया और फिर संस्कारों का हिस्सा बनकर पीढ़ियों तक चलता रहा। आज भी अनेक परिवार इन नियमों को सम्मान और अनुशासन की दृष्टि से देखते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। "अतिथि देवो भवः" का सिद्धांत यह सिखाता है कि घर आने वाले मेहमान का स्वागत देवता के समान किया जाना चाहिए। जब किसी अतिथि को भोजन कराया जाता है तो उसमें केवल स्वाद का ही नहीं बल्कि सम्मान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। भोजन परोसने का विनम्र तरीका इस सम्मान को और अधिक स्पष्ट करता है। दोनों हाथों से थाली पकड़ना, झुककर भोजन देना और आदरपूर्वक रोटी परोसना भारतीय आतिथ्य की पहचान मानी जाती है। वास्तु शास्त्र में भी भोजन को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं वर्णित हैं। माना जाता है कि जिस घर में भोजन का सम्मान होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भोजन को अनादरपूर्वक परोसना या उसके प्रति लापरवाही दिखाना शुभ नहीं माना जाता। कई लोग विश्वास करते हैं कि भोजन के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने से घर में सुख-समृद्धि और संतोष बना रहता है। यही कारण है कि भोजन परोसने की छोटी-छोटी बातों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। अन्न के महत्व को समझने के लिए किसान की मेहनत को याद करना आवश्यक है। खेत में बीज बोने से लेकर फसल काटने तक किसान अनगिनत कठिनाइयों का सामना करता है। इसके बाद अनाज मंडी तक पहुंचता है, फिर पिसाई होती है और अंत में वह रोटी के रूप में हमारी थाली तक आता है। इस पूरी प्रक्रिया में अनेक लोगों का श्रम और समय जुड़ा होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में भोजन को व्यर्थ न करने और उसका सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है। रोटी को सम्मानपूर्वक परोसने की परंपरा भी इसी सोच का विस्तार मानी जा सकती है। आज के आधुनिक दौर में विज्ञान और तकनीक ने जीवन को काफी बदल दिया है। कई पारंपरिक मान्यताओं को लोग तर्क और वैज्ञानिक दृष्टि से देखने लगे हैं। यह सत्य है कि केवल बाएं हाथ से रोटी परोसने से किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने या आर्थिक नुकसान होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन परंपराओं का महत्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि उनका उद्देश्य लोगों में अनुशासन, स्वच्छता, सम्मान और कृतज्ञता जैसे मूल्यों को बनाए रखना है। दादी-नानी की सीखों में जीवन का गहरा अनुभव छिपा होता है। वे केवल नियम नहीं बतातीं बल्कि उनके माध्यम से जीवन जीने का तरीका भी सिखाती हैं। भोजन को सम्मान देना, उसे व्यर्थ न करना, प्रेमपूर्वक परोसना और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना ऐसे मूल्य हैं जो किसी भी समाज को मजबूत बनाते हैं। जब बच्चे इन बातों को बचपन से सीखते हैं तो उनके भीतर संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। भोजन से जुड़ी परंपराएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में छोटी-छोटी बातों का भी महत्व होता है। किसी को आदरपूर्वक पानी देना, मुस्कुराकर भोजन परोसना या धन्यवाद के भाव के साथ भोजन ग्रहण करना सामान्य बातें लग सकती हैं, लेकिन यही व्यवहार समाज में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाते हैं। भारतीय संस्कृति ने हमेशा बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक भावनाओं को महत्व दिया है और भोजन परोसने की परंपराएं उसी सोच को दर्शाती हैं।

अंततः यह कहा जा सकता है कि रोटी परोसने से जुड़ी यह मान्यता केवल हाथों के उपयोग का विषय नहीं है, बल्कि सम्मान, सेवा, कृतज्ञता और संस्कारों की अभिव्यक्ति है। चाहे कोई व्यक्ति इन बातों को धार्मिक दृष्टि से देखे या सांस्कृतिक परंपरा के रूप में स्वीकार करे, उनका मूल संदेश सकारात्मक और प्रेरणादायक है। भोजन के प्रति आदर का भाव हमें विनम्र बनाता है, दूसरों के श्रम का सम्मान करना सिखाता है और जीवन में संतोष की भावना विकसित करता है। यही कारण है कि आज भी भारतीय परिवारों में बुजुर्ग बच्चों को याद दिलाते हैं कि भोजन केवल खाने की वस्तु नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है और उसे हमेशा सम्मान तथा प्रेम के साथ परोसा जाना चाहिए।

राजनीतिक अस्थिरता से घिरा ब्रिटेन

ब्रिटेन के लिए इस सप्ताह की शुरुआत प्रधानमंत्री पद से किएर स्टार्मर के इस्तीफे के साथ हुई। उनका इस्तीफा राजनीतिक नियति की चौंकाने वाली गति को ही दर्शाता है, क्योंकि दो साल पहले ही वे करीब दो दशकों बाद लेबर पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी के नायक बनकर उभरे थे। वैसे तो राजनीति का स्वरूप निर्मम ही कहा जाता है, लेकिन हाल के दौर में ब्रिटिश राजनीति में निर्ममता का यह भाव कहीं ज्यादा बढ़ा है और उसी के ताजा शिकार हुए हैं स्टार्मर। स्टार्मर के इस प्रकार पद छोड़ने की घटना ने देश की राजनीति में गहरी बुनियादी चुनौतियों को रेखांकित करने का ही काम किया है।

स्टार्मर ने इस्तीफा देते समय कहा कि राष्ट्रीय हित सदैव निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर होने चाहिए, लेकिन त्यागपत्र के पीछे की राजनीतिक मजबूरियों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। मई में हुए स्थानीय और क्षेत्रीय चुनावों में लेबर पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन और फिर उपचुनाव में मिली करारी हार ने सरकार और मतदाताओं के बीच बढ़ते फासले को उजागर करने का काम किया। दो साल पहले पार्टी को जो मजबूत जनादेश मिला, वह समय के साथ कमजोर पड़ता दिखने लगा, क्योंकि सुस्त आर्थिक विकास, महंगाई के दबाव से जीवनयापन में आ रही मुश्किलों से जनता का एक बड़ा वर्ग यही सोचने लगा कि लेबर पार्टी की सरकार उनके जीवन में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं ला पाई। जनता के इस मोहभंग से पार्टी की तंद्रा टूटी और आंतरिक विरोध के कुछ स्वर मुखर होने लगे। अंततः स्टार्मर पर यह दबाव डाला जाने लगा कि या तो वे नेतृत्व की शैली बदलें या फिर नए नेता के लिए जगह खाली करें। छिटपुट आलोचना से शुरू हुआ यह सिलसिला व्यापक विद्रोह का रूप लेता गया, जो दलगत एकता के नाजुक ढांचे को भी रेखांकित करता है कि संसदीय बहुमत के बाद भी यह बात बेमानी ही साबित होती है। नीतिगत विवादों ने भी स्टार्मर की स्थिति को और कमजोर किया। कल्याणकारी सुधारों के अलावा पीटर मैंडेलसन जैसे विवादित व्यक्ति की नियुक्ति को लेकर बखेड़ा और रक्षा खर्च पर मतभेदों ने भी पार्टी के भीतर की दरारों को उजागर कर दिया। इसमें सबसे अधिक विवादास्पद सरकार का वह कदम था, जिसके तहत वर्ष 2030 तक रक्षा व्यय को नाटो के मानकों के अनुरूप अपनी जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाना था। वित्तीय स्रोतों पर उठे सवालों और घरेलू प्राथमिकताओं के आपसी टकराव से लेबर पार्टी में समीकरण बिगड़े। कुछ मंत्रियों के इस्तीफे भी हुए, जिससे यह धारणा मजबूत होती गई कि सरकार अपनी महत्वाकांक्षाओं और आर्थिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन साधने में संघर्ष कर रही है। इसके बावजूद स्टार्मर की इस तरह विदाई किसी विडंबना से कम नहीं, क्योंकि उनके खाते में कुछ उपलब्धियां भी रहीं। जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की प्रतीक्षा सूची के बोझ को घटाना, श्रमिक अधिकारों को सुदृढ़ बनाना और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ स्थायित्व ने नीतिगत स्तर पर परिणामों को पुष्ट किया। हालांकि जनता की अत्यधिक बढ़ती आकांक्षाओं और सिमटते राजनीतिक धैर्य के इस दौर में ऐसी क्रमिक और छोटी सफलताएं अक्सर राजनीतिक पूंजी में रूपांतरित नहीं हो सकीं।

स्टार्मर ने खुद को शासन चलाने के बोझ और लेबर पार्टी की प्रचंड जीत से पैदा हुई जनता की उम्मीदों के दोहरे दबाव के द्वंद्व से जूझते हुए पाया।

स्टार्मर का इस्तीफा ब्रिटेन में पिछले कुछ समय से नेतृत्व परिवर्तन में अस्थिरता के पड़ाव में एक नया अध्याय ही जोड़ता है। 2016 में ब्रेक्जिट के बाद से ब्रिटेन में जिस प्रकार प्रधानमंत्री आते और जाते गए, उसने राजनीतिक स्थायित्व, संस्थागत लचीलेपन और दीर्घकालिक नीतिगत एजेंडे को बनाए रखने की सरकारों की क्षमता पर व्यापक सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अब सभी का ध्यान इन पहलुओं से इतर नए नेतृत्व की तलाश पर केंद्रित होगा। एंडी बर्नहैम प्रधानमंत्री पद के तगड़े दावेदार बनकर उभरे हैं। लेबर पार्टी के दिग्गज क्षत्रपों में गिने जाने वाले बर्नहैम की राजनीतिक पहचान की जड़ें सत्ता के विकेंद्रीकरण, क्षेत्रीय सशक्तीकरण और उत्तरी इंग्लैंड की पुरजोर वकालत से जुड़ी रही हैं। संसद में उनकी हालिया वापसी और वेस स्ट्रीटिंग और डेविड लैमी जैसी प्रभावशाली हस्तियों से मिले समर्थन ने उनके दावे को और मजबूती दी है। नेतृत्व की होड़ में वैसे तो और भी दावेदार हैं, लेकिन सितंबर में संसदीय सत्र के दोबारा शुरू होने से पहले समर्थन जुटाकर बाजी अपने नाम करने के लिहाज से बर्नहैम ही सबसे अनुकूल स्थिति में दिख रहे हैं।

स्टार्मर के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने के चलते सामरिक-आर्थिक से लेकर नीतिगत एवं कल्याणकारी सुधारों को लेकर सरकारी कामकाज में सुस्ती आ सकती है। हालांकि संसद में लेबर पार्टी का व्यापक बहुमत यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार की स्थिति किसी लिहाज से कमजोर न हो और न ही संसदीय चुनाव की कोई आहट सुनाई देगी। लेबर से इतर प्रतिद्वंद्वी दलों के दृष्टिकोण से देखें तो स्टार्मर का इस्तीफा कंजरवेटिव और रिफार्म यूके पार्टी को नया हौसला देगा। लेबर पार्टी की इन मुश्किलों का कंजरवेटिव पार्टी अपने लिए माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी तो निगेल फराज की रिफार्म यूके घुसपैठ, आर्थिक प्रदर्शन और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर आक्रामक होकर सरकार और लेबर पार्टी को घेरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

अभियान

राजभोग से बढ़कर थी एक भक्त की खिचड़ी: जब भगवान जगन्नाथ ने दुनिया को सिखाया प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा

भारतीय सनातन परंपरा में भगवान और भक्त के संबंध को केवल आराधना या पूजा-पाठ तक सीमित नहीं माना गया है। यह संबंध प्रेम, विश्वास, समर्पण और आत्मीयता की उस डोर से बंधा हुआ है, जो किसी भी सांसारिक रिश्ते से कहीं अधिक गहरी और पवित्र होती है। हमारे धर्मग्रंथों, पुराणों और लोककथाओं में ऐसे असंख्य प्रसंग मिलते हैं, जिनमें भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि उन्हें बाहरी वैभव, सोना-चांदी, महंगे भोग और बड़े-बड़े अनुष्ठानों से अधिक अपने भक्त का निष्कपट प्रेम प्रिय है। यही कारण है कि कभी भगवान राम शबरी के जूठे बेर ग्रहण करते हैं, कभी भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा के सूखे चावल खाकर भाव-विभोर हो जाते हैं और कभी भगवान जगन्नाथ एक साधारण भक्त महिला की खिचड़ी के लिए राजसी भोग तक का मोह छोड़ देते हैं। माता कर्मा बाई और भगवान जगन्नाथ की कथा इसी दिव्य सत्य को उजागर करती है कि भगवान का हृदय प्रेम से जीता जा सकता है, नियमों और दिखावे से नहीं।

लोकमान्यताओं के अनुसार माता कर्मा बाई भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की परम भक्त थीं। उनका जीवन भक्ति, सरलता और मातृत्व भाव का अद्भुत संगम था। वे भगवान को किसी दूर बैठे देवता की तरह नहीं देखती थीं, बल्कि उन्हें अपना पुत्र मानती थीं। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे के सुख-दुख, भूख-प्यास और आराम की चिंता करती है, उसी प्रकार कर्मा बाई भी हर समय अपने ठाकुर जी के बारे में सोचती रहती थीं। उनके लिए भगवान केवल पूजा के पात्र नहीं थे, बल्कि परिवार के सबसे प्रिय सदस्य थे।

कहा जाता है कि कर्मा बाई का दिन भगवान के स्मरण से शुरू होता था। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले उन्हें अपने ठाकुर जी की चिंता होती थी। वे सोचती थीं कि कहीं मेरा बच्चा भूखा तो नहीं होगा, कहीं उसे भोजन की प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ रही होगी। यही भाव उनके मन में इतना गहरा था कि उन्होंने भगवान की सेवा को अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म बना लिया था। एक दिन उनके मन में विचार आया कि वे भगवान को प्रतिदिन चढ़ाए जाने वाले सामान्य भोग के स्थान पर अपने हाथों से बनी खिचड़ी खिलाएं। यह विचार किसी धार्मिक नियम या विशेष अनुष्ठान से प्रेरित नहीं था। यह तो एक मां के प्रेम का स्वाभाविक परिणाम था। उन्हें लगा कि जैसे मां अपने बच्चे को घर का ताजा और स्नेह से बना भोजन खिलाती है, वैसे ही उन्हें भी अपने ठाकुर जी को अपने हाथों की खिचड़ी खिलानी चाहिए।

अगली सुबह वे उठीं और बिना किसी औपचारिकता के सीधे रसोई में चली गईं। उन्होंने स्नान नहीं किया, लंबी पूजा नहीं की और न ही किसी विशेष विधि-विधान की चिंता की। उनके मन में केवल एक ही बात थी कि भगवान को भूखा नहीं रखना है। उन्होंने प्रेम और श्रद्धा से खिचड़ी बनाई और उसे भगवान को अर्पित कर दिया। लोककथाओं में वर्णन मिलता है कि भगवान जगन्नाथ उस खिचड़ी के स्वाद से नहीं, बल्कि उसमें समाए प्रेम से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अत्यंत आनंदपूर्वक स्वीकार किया।

कहा जाता है कि भगवान ने माता कर्मा बाई से कहा कि उन्हें यह खिचड़ी अत्यंत प्रिय है और वे प्रतिदिन इसे ग्रहण करने आएंगे। यह सुनकर कर्मा बाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद यही बन गया कि वे हर सुबह भगवान के लिए खिचड़ी तैयार करें और उन्हें प्रेमपूर्वक भोग लगाएं।

समय बीतता गया और यह क्रम नियमित रूप से चलता रहा। कर्मा बाई प्रतिदिन सुबह सबसे पहले भगवान के लिए खिचड़ी बनातीं। उनके लिए यह कोई धार्मिक कर्म नहीं बल्कि अपने पुत्र के प्रति एक मां का कर्तव्य था। वे भगवान को खिलाकर ही स्वयं संतुष्ट होती थीं। उनके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि वे कोई विशेष साधना कर रही हैं। वे तो केवल प्रेम की भाषा समझती थीं और उसी भाषा में भगवान की सेवा करती थीं।

एक दिन एक साधु उनके घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कर्मा बाई बिना स्नान किए भगवान को भोग अर्पित कर रही हैं। साधु को यह बात उचित नहीं लगी। उन्होंने कर्मा बाई को समझाया कि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पहले स्नान करना चाहिए, फिर पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। साधु ने कहा कि बिना शुद्धि और विधि-विधान के भोग लगाना उचित नहीं माना जाता।

कर्मा बाई अत्यंत विनम्र और सरल स्वभाव की थीं। उन्होंने साधु की बात को आदरपूर्वक स्वीकार किया। उन्हें लगा कि शायद वे अब तक अनजाने में कोई गलती करती रही हैं। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अगले दिन से वे साधु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करेंगी।

अगले दिन जब सुबह हुई तो कर्मा बाई ने सबसे पहले स्नान किया। फिर पूजा की तैयारी की, मंत्रों का जाप किया और अन्य धार्मिक क्रियाएं पूरी कीं। इन सब कार्यों में काफी समय लग गया। जब तक वे रसोई में पहुंचीं और खिचड़ी तैयार की, तब तक पहले की अपेक्षा काफी देर हो चुकी थी।

उधर लोककथा के अनुसार उसी समय पुरी में भगवान जगन्नाथ असामान्य रूप से व्याकुल दिखाई देने लगे। मंदिर में प्रतिदिन की तरह राजसी भोग की तैयारी चल रही थी। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भगवान के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले थे, लेकिन भगवान का मन कहीं और था। वे बार-बार किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कहा जाता है कि उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी और वे बेचैन होकर मानो किसी प्रिय वस्तु की राह देख रहे थे।

मंदिर के सेवकों और पुजारियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान इतने व्याकुल क्यों हैं। राजभोग तैयार था, पूजा की सारी व्यवस्थाएं पूरी थीं, फिर भी भगवान का मन प्रसन्न नहीं था। लोककथा कहती है कि भगवान को अपनी भक्त मां कर्मा बाई के हाथों की खिचड़ी का इंतजार था। उनके लिए वह साधारण खिचड़ी किसी भी राजसी व्यंजन से अधिक मूल्यवान थी क्योंकि उसमें प्रेम, वात्सल्य और समर्पण का स्वाद मिला हुआ था।

कहा जाता है कि उसी रात भगवान ने उस साधु को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने उनसे कहा कि तुमने मेरी भक्त को उन नियमों में बांध दिया है, जिनसे उसका सहज प्रेम प्रभावित हो गया। भगवान ने बताया कि उन्हें कर्मा बाई की खिचड़ी इसलिए प्रिय है क्योंकि वह किसी दिखावे या औपचारिकता से नहीं, बल्कि एक मां के स्नेह से बनाई जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रेम से किया गया अर्पण सबसे श्रेष्ठ होता है।

स्वप्न में भगवान की यह बात सुनकर साधु को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि धर्म का सार केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति है। यदि नियम प्रेम को बाधित करने लगें, तो उनका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अगले दिन साधु स्वयं कर्मा बाई के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि वे पहले की तरह भगवान को प्रेमपूर्वक खिचड़ी अर्पित करें क्योंकि भगवान को वही सबसे अधिक प्रिय है।

कर्मा बाई ने पुनः अपने पुराने क्रम को अपनाया। वे सुबह उठते ही भगवान के लिए खिचड़ी बनातीं और प्रेमपूर्वक भोग लगातीं। लोकविश्वास है कि भगवान जगन्नाथ तब से अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। यही कारण बताया जाता है कि जगन्नाथ परंपरा में खिचड़ी का विशेष महत्व माना जाता है और इसे भक्ति तथा प्रेम का प्रतीक समझा जाता है।

यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देती है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल कठिन अनुष्ठानों और जटिल विधियों से होकर नहीं जाता। सच्चे मन, निष्कपट भाव और प्रेमपूर्ण समर्पण से भी भगवान को पाया जा सकता है। जब मन में अहंकार नहीं होता, जब भक्ति में स्वार्थ नहीं होता और जब सेवा में केवल प्रेम होता है, तब भगवान स्वयं भक्त के समीप आ जाते हैं।

माता कर्मा बाई की कहानी यह भी बताती है कि ईश्वर के लिए किसी वस्तु का मूल्य उसकी कीमत से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना से तय होता है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

'विकास भी, विरासत भी' : रुद्र वीणा निर्माण की परंपरा को राष्ट्रीय गौरव दिलाने वाले श्री किशोरभाई मिस्त्री

▶▶ रुद्र वीणा के निर्माण के लिए श्री किशोरभाई का संगीत नाटक अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन

▶▶ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो ने युवा वर्ग में रुद्र वीणा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई : श्री किशोरभाई मिस्त्री

गांधीनगर : गुजरात की कला नगरी के रूप में विख्यात वडोदरा का मिस्त्री परिवार पिछले 150 वर्षों से दुर्लभ एवं ऐतिहासिक रुद्र वीणा की विरासत को संरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। मिस्त्री परिवार के इन प्रयासों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हुआ है। नई दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी ने रुद्र वीणा निर्माण के लिए श्री किशोरभाई सोमाभाई मिस्त्री का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष-2024 के लिए चयन किया है।

इस सम्मान के लिए चयनित होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में श्री किशोरभाई ने कहा, "यह मेरा सम्मान नहीं है, बल्कि मेरे पूर्वजों की साधना एवं तपस्या का फल है।" अपने हृदय के भाव व्यक्त करते हुए श्री किशोरभाई कहते हैं, "मेरा सम्मान व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि गुजरात की समृद्ध संगीत परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है।"

उल्लेखनीय है कि किशोरभाई पिछले पाँच दशकों से रुद्र वीणा के निर्माण एवं संवर्धन के लिए परिश्रम कर रहे हैं।

यदि श्री किशोरभाई की संगीत यात्रा पर दृष्टि डालें, तो वर्ष 2023 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा उन्हें रुद्र वीणा के निर्माण के लिए 'गुरु' की उपाधि प्रदान की गई थी और गुरु-शिष्य परंपरा के अंतर्गत वे हाल में संगीत साधकों को रुद्र वीणा का निर्माण सिखा रहे हैं। संगीत के बदलते स्वरूप तथा भावी पीढ़ी की रुचि के पर बात करते हुए वे कहते हैं, "वर्ष 2023 में मुझे प्रथम इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो में भाग लेने का अवसर मिला। इस एक्सपो में संगीत प्रेमियों और आगंतुकों ने अत्यधिक रुचि दिखाई, जिसमें युवा वर्ग की उपस्थिति विशेष रूप से ध्यानाकर्षित करने वाली थी।"

श्री किशोरभाई के अनुसार इस एक्सपो में रुद्र वीणा तथा उसके निर्माण के प्रति युवाओं द्वारा दिखाई गई दिलचस्पी अत्यंत उल्लेखनीय थी।

रुद्र वीणा निर्माण की प्रक्रिया और संगीत जगत में उसका महत्व

पिछले पाँच दशकों से रुद्र वीणा निर्माण से जुड़े श्री किशोरभाई मिस्त्री इसकी निर्माण प्रक्रिया समझाते हुए कहते हैं कि रुद्र वीणा की निर्माण प्रक्रिया प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर है। वीणा के दोनों सिरों पर ध्वनि को गुंजायमान बनाने के लिए गोल तुंबे लगाए जाते हैं। ये तुंबे लौकी वेल के कुल की एक विशेष वनस्पति से तैयार होते हैं। यद्यपि यह पौधा पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन रुद्र वीणा के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के तट पर उगने वाले तुंबों का चयन किया जाता है। इन तुंबों को जोड़ने के लिए 'पैसिफिक बांबू' के दंड का उपयोग होता है। इस बाँस को मौसम के अनुसार प्राकृतिक रूप से सुखाया जाता है। इसके बाद गर्म सलाखों की सहायता से बाँस की अंदरूनी गाँठों को जलाकर उसे भीतर से खोखला किया जाता है, जिससे ध्वनि बिना किसी विक्षेप के उसमें से प्रवाहित हो सके। इस वीणा की खूँटियों के के लिए काले शीशम की लकड़ी का उपयोग होता है। शास्त्रों में संगीत के प्रथम स्वर 'षड्ज' (सा) का प्रतीक मोर को माना गया है। इसलिए वीणा पर काले शीशम अथवा सागौन की लकड़ी से आकर्षक मयूर उकेरा जाता है। एक रुद्र वीणा के निर्माण में नक्काशी सहित लगभग दो से तीन वर्षों का समय लगता है।

मिस्त्री परिवार वडोदरा के वेराई माता चौक, खंडेराव मार्केट के निकट स्थित अपनी 153 वर्ष पुरानी दुकान में रुद्र वीणा का निर्माण करता है। यहाँ निर्मित सितार मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम-न्यूयॉर्क-यूएसए में, सरस्वती वीणा हॉलैंड के संग्रहालय में, रुद्र वीणा बरोडा म्यूज़ियम एवं फ्रांस म्यूज़ियम जैसे विश्व के प्रतिष्ठित संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं। इसके अतिरिक्त; गुजरात के वडनगर में निर्माणाधीन भव्य संगीत संग्रहालय के लिए इस परिवार ने लगभग 31 परंपरागत संगीत वाद्य तैयार किए हैं।

रुद्र वीणा निर्माण प्रक्रिया में मिस्त्री परिवार का आगमन कैसे हुआ ?

इस तंतु वाद्य के निर्माण की कला मिस्त्री परिवार ने कैसे प्रवेश किया, इसकी कहानी रोचक है। किशोरभाई मिस्त्री बताते हैं कि उनके परदादा श्री मनसुख रघुनाथजी, गायकवाड दरबार के प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक एम. सी. बुआ से संगीत सीखने जाते थे। एक बार संयोगवश गुरुजी की वीणा टूट गई। उस समय वडोदरा में इस वाद्य की मरम्मत करने वाला कोई कारीगर उपलब्ध नहीं था। तब मनसुख रघुनाथजी ने अपनी सूझबूझ और कौशल से उस वाद्य की इतनी श्रेष्ठ मरम्मत की कि गुरुजी भी आश्चर्यचकित हो गए। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, "यह वाद्य इतनी सुंदरता से सुधारा गया है कि इसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती। अब आप इसे देखकर एक नया वाद्य बनाइए।" गुरुजी के इन शब्दों का सम्मान करते हुए मनसुखजी ने प्रयास किया और इस प्रकार लगभग 153 वर्ष पूर्व इस परिवार का वाद्य निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश हुआ।

शाला प्रवेशोत्सव-2026

भिक्षावृत्ति मुक्त एवं वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का अनूठा प्रयास

▶▶ थलतेज में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में आयोजित हुआ शाला प्रवेशोत्सव

▶▶ विकसित भारत @2047 के संकल्प को साकार करने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

गांधीनगर : नगर प्राथमिक शिक्षा समिति, अहमदाबाद द्वारा थलतेज स्थित पीएम श्री थलतेज अनुपम प्राथमिक विद्यालय में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति में बुधवार को 'शाला प्रवेशोत्सव-2026' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए, 'सिग्नल स्कूल' में अध्ययनरत तथा नवप्रवेशी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रवेशोत्सव आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम अंतर्गत भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए 20 बच्चों, 'सिग्नल स्कूल' के 233 बच्चों तथा विद्यालय के 50 नवप्रवेशी विद्यार्थियों सहित कुल 303 बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि वंचित एवं भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को शिक्षा का अधिकार तथा समान अवसर प्रदान करने का यह प्रयास समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से अब तक कुल 276 बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराकर 'सिग्नल शाला' तथा अन्य सरकारी विद्यालयों में शिक्षा से जोड़ा गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों से बच्चों को लाकर उनसे भिक्षावृत्ति करवाने वाले अंतरराज्यीय रैकेट के विरुद्ध कार्रवाई कर 33 बच्चों को मुक्त कराया गया तथा उनका उनके परिवारों के साथ पुनर्मिलन कराया गया है। उन्होंने शिक्षकों से इन बच्चों को अपने बच्चों के समान स्नेह, मार्गदर्शन एवं संस्कार देने की अपील की।

उन्होंने उपस्थित नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने तथा सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर अहमदाबाद नगर निगम आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि ने कहा कि अहमदाबाद शहर में पुलिस, महानगर पालिका तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त प्रयासों से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री के करकमलों से भिक्षावृत्ति मुक्ति तथा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक श्री जी.एस. मलिक, सदस्य सचिव श्रीमती हेतल एम. पवार, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलेशभाई पटेल, शहर अध्यक्ष श्री प्रेरकभाई शाह, गुजरात कानूनी सेवा प्राधिकरण के प्रोजेक्ट अधिकारी डॉ. एम.ए. पीपराणी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

अहमदाबाद मंडल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित; ई पत्रिका 'आश्रम सौरभ' के 55वें अंक का विमोचन

पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद में दिनांक 24.06.2026 को मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री वेद प्रकाश की अध्यक्षता में 'मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति' की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मंडल की ई-पत्रिका 'आश्रम सौरभ' के 55वें अंक का विमोचन किया गया।

प्रेमचंद जयंती एवं प्रश्न-मंच का आयोजन

बैठक से पूर्व हिंदी साहित्य के युगप्रवर्तक प्रेमचंद जी की जयंती मनाई गई। राजभाषा विभाग द्वारा उनके जीवनवृत्त एवं साहित्य पर एक रोचक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर आयोजित 'हिंदी प्रश्न-मंच' में रेलकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिसमें विजेताओं को मंडल रेल प्रबंधक द्वारा पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा के उत्कृष्ट प्रयोग हेतु सम्मान

सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'राजभाषा रत्न' प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मंडल के 08 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्रदान सम्मानित किया गया।

दैनिक कार्यों में सरल हिंदी के प्रयोग पर जोर

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने अपने संबोधन में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की कि वे निर्धारित लक्ष्यों से आगे बढ़कर राजभाषा हिंदी में अधिकाधिक कार्य सुनिश्चित करें तथा इसके प्रयोग को और अधिक सहज एवं प्रभावी बनाने पर ज़ोर दें।

मण्डल के सभी विभागों की टीमें तैयार कर उनके मध्य मण्डल स्तरीय प्रश्नोतरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिससे राजभाषा के प्रचार प्रसार को गति मिलेगी। उन्होंने कहा, "राजभाषा केवल पत्राचार की भाषा नहीं है, बल्कि संवाद को जीवंत और पारदर्शी बनाने का एक सशक्त माध्यम है। जब हम दैनिक कार्यों में आम बोलचाल की सरल हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो इससे न केवल कार्यों के निष्पादन में गति आती है, बल्कि आम जनता और रेल यात्रियों के साथ हमारा जुड़ाव भी और अधिक मजबूत होता है। हमें इसे केवल एक औपचारिक दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि अपनी सहज कार्यशैली का अभिन्न अंग बनाना चाहिए।"

बैठक में अपर मंडल राजभाषा अधिकारी श्रीमती मंजू मीणा, राजभाषा अधिकारी (प्रभारी) श्री हाफिज अली खान सहित मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

'कन्या केळवणी महोत्सव एवं शाला प्रवेशोत्सव - 2026'

दूसरे दिन 8 हजार से अधिक गांव और 11 हजार से अधिक शालाएं बनी शिक्षा उत्सव की साक्षी

दो दिनों में राज्यभर में कुल 11.20 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने स्कूलों में नामांकन कराया

गांधीनगर : 'कन्या केळवणी महोत्सव एवं शाला प्रवेशोत्सव – 2026' के दूसरे दिन यानी 24 जून को राज्यभर में कुल 8,173 गांवों तथा 11,987 स्कूलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, पदाधिकारी एवं उच्च अधिकारियों सहित कुल 29,682 महानुभावों ने विभिन्न स्कूलों का दौरा कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस प्रकार, पिछले दो दिनों में राज्यभर के कुल 17,338 गांवों, 60,184 महानुभावों तथा 24,716 स्कूलों को शामिल करते हुए कुल 11.20 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन किया गया है।

गुजरात में साक्षरता दर बढ़ाने तथा राज्य के प्रत्येक बच्चे का 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'कन्या केळवणी महोत्सव एवं शाला प्रवेशोत्सव – 2026' की 24वीं कड़ी का गत दिवस मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल के करकमलों द्वारा वडनगर की ऐतिहासिक बीएन हाईस्कूल से राज्यव्यापी शुभारंभ किया गया। इस शैक्षणिक महापर्व की शुरुआत उस स्थान से की गई, जहां देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन तथा शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रिवाबा जाडेजा के नेतृत्व में राज्य का एक भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे; इसके लिए राज्य सरकार संपूर्णतः कटिबद्ध है। शिक्षा के इस महापर्व के दौरान नई पीढ़ी के लाखों बच्चों ने स्कूलों में प्रवेश प्राप्त कर रिकॉर्ड ब्रेक नामांकन दर्ज कराया है। प्रवेशोत्सव के दौरान आंगनवाड़ी एवं बालमंदिरों में 62 हजार से अधिक बच्चों ने अक्षरज्ञान का श्रीगणेश किया। बालवाटिका में कुल 1,39,925 प्रवेश-पात्र बच्चों के मुकाबले कुल 1.40 लाख से अधिक नए नामांकन दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त; कक्षा-1 में 34 हजार से अधिक, कक्षा-9 में 1,96,755, कक्षा-11 में 1,01,759 विद्यार्थी तथा 'बैक टू स्कूल सर्वे' के अनुसार 21,892 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रवेश प्राप्त कर शाला प्रवेशोत्सव को वास्तविक अर्थों में सफल बनाया है।

तदुपरांत; दूसरे दिन राज्य सरकार द्वारा 847 स्कूलों में नवीन परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त; कन्या केळवणी को और अधिक गति देने के लिए प्रवेशोत्सव के दौरान राज्य की 5,664 प्रतिभाशाली कन्याओं को 'विद्यालक्ष्मी बॉन्ड' प्रदान कर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

राज्य की उदार जनता ने इस शिक्षा यज्ञ को लोकोत्सव का स्वरूप देते हुए खुले हाथों से सहयोग दिया है। इस अभियान के दौरान जनभागीदारी के रूप में कुल 9.19 करोड़ रुपए से अधिक की उल्लेखनीय सहायता प्राप्त हुई है। इसमें 1.25 करोड़ रुपए से अधिक नकद स्वरूप में तथा 7.95 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के विभिन्न शैक्षणिक उपकरण स्कूलों को भेंटस्वरूप प्रदान किए गए हैं।

'कन्या केळवणी महोत्सव एवं शाला प्रवेशोत्सव – 2026' केवल एक कार्यक्रम नहीं; बल्कि शिक्षा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता, समाज की सहभागिता तथा उज्ज्वल भविष्य की ओर गुजरात के मजबूत संकल्प का जीवंत प्रतीक बन रहा है।

छोटाउदेपुर: आदिवासी कौशल से वैश्विक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग तक गुजरात की नई छलांग

▶▶ VGRC मध्य गुजरात 2026 में प्रस्तुत होगा बांस आधारित स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हब का विज़न

▶▶ खेल, रोजगार और आदिवासी उद्यमिता को जोड़ने वाली विकास की नई कहानी

गांधीनगर : माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में खेलों को नई पहचान मिली है जहाँ खेल अब केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित न रहकर आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और युवाओं के सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक ओर राज्य विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना विकसित कर रहा है, तो दूसरी ओर खेल आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य भी कर रहा है।

इसी सोच का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मध्य गुजरात के छोटाउदेपुर जिले में विकसित किया जा रहा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल को वैश्विक अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक अभिनव पहल बनकर उभर रहा है।

VGRC मध्य गुजरात में आकर्षण का केंद्र बनेगा छोटाउदेपुर मॉडल

वडोदरा स्थित GSFC यूनिवर्सिटी में 29 और 30 जून 2026 को आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) मध्य गुजरात में छोटाउदेपुर के इस महत्वाकांक्षी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हब को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों के समक्ष जिले में उपलब्ध बांस संसाधन, कुशल मानव-शक्ति, संभावित औद्योगिक क्लस्टर विकास तथा वैश्विक बाजारों से जुड़ने की संभावनाओं को विस्तार से रखा जाएगा।

यह पहल केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं है बल्कि आदिवासी कौशल, स्थानीय उद्यमिता और आधुनिक अर्थव्यवस्था के बीच एक सशक्त सेतु स्थापित करने का प्रयास भी है। यदि यहाँ बांस आधारित उत्पाद निर्माण से लेकर ब्रांडिंग और विपणन तक की पूरी मूल्य श्रृंखला स्थानीय स्तर पर विकसित होती है, तो छोटाउदेपुर भविष्य में टिकाऊ औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक सफल मॉडल बन सकता है।

क्या है छोटाउदेपुर मॉडल की विशेषता?

छोटाउदेपुर लंबे समय से बांस शिल्प, लकड़ी के काम और पारंपरिक कारीगरी के लिए जाना जाता है। अब इन्हीं पारंपरिक कौशलों को आधुनिक डिज़ाइन, नई तकनीकों और वैश्विक बाजार की मांगों के अनुरूप विकसित कर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट निर्माण से जोड़ने की दिशा में योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं।

दुनिया भर में पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। क्रिकेट बैट, स्टंप्स, प्रशिक्षण उपकरण, आउटडोर गेम्स एक्सेसरीज़ और अन्य खेल सामग्रियों में बांस तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। छोटाउदेपुर के पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और स्थानीय कारीगरों का अनुभव इस अवसर को एक सशक्त उद्योग में बदलने की क्षमता रखता है।

इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 'सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग' और 'कल्चरल ब्रांडिंग' दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जा रहा है। बांस आधारित उत्पाद, हल्के वजन वाली सामग्री और पुनर्चक्रण योग्य घटकों का उपयोग आज वैश्विक खेल उद्योग की नई आवश्यकता बनता जा रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2024 में स्मार्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाजार का आकार लगभग 3.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2030 तक 10.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की संभावना रखता है। सेंसर आधारित गेंदों, स्मार्ट रैकेट और वेयरेबल फिटनेस तकनीकों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?

वर्ष 2024 में वैश्विक खेल उपकरण बाजार का आकार लगभग 407 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में निरंतर विस्तार की भी संभावना है। भारत में वर्तमान में 300 से अधिक प्रकार के खेल उपकरणों का उत्पादन किया जाता है। देश का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाजार वर्ष 2023 में लगभग 24.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका था और वर्ष 2030 तक इसमें 13 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि का अनुमान है। ऐसे समय में नए उत्पादन केंद्रों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है और छोटाउदेपुर इस दिशा में एक संभावित उभरते केंद्र के रूप में देखा जा रहा है।

स्थानीय युवाओं और कारीगरों के लिए खुल सकते हैं नए अवसर

इस पहल का सबसे बड़ा लाभ स्थानीय युवाओं, महिलाओं, कारीगरों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मिलने की संभावना है। कच्चे माल की उपलब्धता से लेकर उत्पादन, डिज़ाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन तक की पूरी प्रक्रिया में स्थानीय भागीदारी बढ़ेगी।

इसके साथ ही स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान, स्पोर्ट्स टूरिज्म ज़ोन और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के विकास की दिशा में भी रोडमैप तैयार किया गया है। वर्तमान में देश में खेल एवं स्पोर्ट्स अपैरल क्षेत्र से 5 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में छोटाउदेपुर जैसे जिले में इस क्षेत्र का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार को नई गति दे सकता है।

खेल विकास को व्यापक दृष्टि से देख रहा है गुजरात

गुजरात सरकार खेलों को केवल प्रतिस्पर्धा या मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देख रही है। खेल महाकुंभ, विद्यालय आधारित खेल कार्यक्रमों और खिलाड़ियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत बनाया जा रहा है।

वर्ष 2010 में जहां खेल महाकुंभ में लगभग 16 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, वहीं वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर लगभग 71 लाख तक पहुंच गई है। राज्य की 230 से अधिक विद्यालयों में 1.21 लाख से अधिक बच्चों को खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

खेल क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में 1,331 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अहमदाबाद में प्रस्तावित 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को ध्यान में रखते हुए विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना और आधुनिक परिवहन सुविधाओं के विकास हेतु 1,278 करोड़ से अधिक की विशेष योजना तैयार की गई है।

अहमदाबाद में विकसित हो रहा सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, भाट में प्रस्तावित ओलंपिक विलेज, नारणपुरा का वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा कराई में निर्माणाधीन एथलेटिक्स स्टेडियम इस व्यापक दृष्टिकोण के प्रमुख उदाहरण हैं। परंपरा और तकनीक, प्राकृतिक संसाधनों और वैश्विक बाजार, स्थानीय कारीगरों और आधुनिक उद्योग के इस अनूठे संगम के साथ छोटाउदेपुर का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हब गुजरात की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह पहल न केवल खेल उद्योग को नई संभावनाएं देगी, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बन सकती है।

पश्चिम रेलवे ने ट्रेन संख्या 09055/09056 बांद्रा टर्मिनस–उधना स्पेशल ट्रेन को किया नियमित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा बांद्रा टर्मिनस और उधना के बीच नियमित रेल संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ट्रेन संख्या 09055/09056 बांद्रा टर्मिनस – उधना स्पेशल को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। यह सेवा संशोधित ट्रेन संख्या 19055/19056 बांद्रा टर्मिनस – उधना – बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस के रूप में परिचालित की जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह स्पेशल ट्रेन 1 अगस्त, 2026 से ट्रेन संख्या 19055/19056 बांद्रा टर्मिनस – उधना एक्सप्रेस के रूप में परिचालित होगी।

ट्रेन संख्या 19055 बांद्रा टर्मिनस – उधना एक्सप्रेस प्रतिदिन बांद्रा टर्मिनस से 09.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 15.05 बजे उधना पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 19056 उधना – बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस प्रतिदिन उधना से 15.45 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 21.35 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में अंधेरी, बोरीवली, वसई रोड, विरार, वैतरणा, सफाले, केलवे रोड, पालघर, बोईसर, वानगांव, दहानू रोड, घोलवड, बोर्डी रोड, उमरगाम रोड, संजान, भिलाड, करंबेली, वापी, वलसाड, बिलिमोरा, वेडछा तथा नवसारी स्टेशनों पर ठहरेगी।

ट्रेन संख्या 19055 बांद्रा टर्मिनस – उधना एक्सप्रेस को भायंदर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 19056 उधना – बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को उदवाडा, पारडी तथा अतुल स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

इस ट्रेन में एसी चेयर कार, सेकेंड सीटिंग तथा जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09055/09056 बांद्रा टर्मिनस – उधना स्पेशल में आरक्षण कराने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया संशोधित ट्रेन संख्या को ध्यान में रखें, क्योंकि यह ट्रेन 1 अगस्त, 2026 से ट्रेन संख्या 19055/19056 के रूप में परिचालित होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय तथा कोच संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

प्रत्येक शुक्रवार को भावनगर टर्मिनस–शकूर बस्ती के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 31 जुलाई तक विस्तारित

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा ग्रीष्मकालीन एवं त्योहारी सीजन-2026 के दौरान विशेष किराये पर संचालित की जा रही ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) श्रेणी की विशेष रेलगाड़ियों की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में भावनगर मंडल से संचालित भावनगर टर्मिनस–शकूर बस्ती साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे भी विस्तारित किए गए हैं।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर मंडल श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित विशेष ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई है:

ट्रेन संख्या 09257 भावनगर टर्मिनस–शकूर बस्ती साप्ताहिक स्पेशल

यह ट्रेन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 जून, 2026 तक संचालित की जानी थी। अब इसकी अवधि बढ़ाकर 31 जुलाई, 2026 तक कर दी गई है। यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को भावनगर टर्मिनस से दोपहर 14:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन शनिवार को प्रातः 10:55 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09258 शकूर बस्ती–भावनगर टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल

यह ट्रेन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 27 जून, 2026 तक संचालित की जानी थी। अब इसकी अवधि बढ़ाकर 01 अगस्त, 2026 तक कर दी गई है। यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार को शकूर बस्ती से दोपहर 13:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रविवार को प्रातः 08:50 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09257 के विस्तारित फेरों के लिए आरक्षण 25 जून, 2026 से सभी कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पूर्व ट्रेन के समय, ठहराव तथा संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक पूछताछ वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

पश्चिम रेल्वे द्वारा भावनगर टर्मिनस ⇌ शकूरबस्ती के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढाए जाएंगे

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	चलाने के दिन	से विस्तृत
09257	भावनगर टर्मिनस – शकूरबस्ती	शुक्रवार	31.07.2026
09258	शकूरबस्ती - भावनगर टर्मिनस	शनिवार	01.08.2026

ठहराव के समय और ट्रेन की बनावट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं।

ट्रेन नंबर 09257 के बढ़ाए गए फेरों के लिए बुकिंग दि.25.06.2026 से सभी PRS काउंटरों और RCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। यह ट्रेन स्पेशल किराए के साथ स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाईक और फोलो करें
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें

शाला प्रवेशोत्सव-2026 : दूसरा दिन

आदिजाति क्षेत्रों से निरक्षरता का कलंक मिटाने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरु कराया गया शाला प्रवेशोत्सव आज शिक्षा क्षेत्र में विकास का वटवृक्ष बना है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आदिजाति जिले दाहोद के मोटी खरज, राहडुंगरी तथा गांगरडा गाँवों में 300 से अधिक बच्चों का शाला प्रवेश कराया

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- शाला प्रवेशोत्सव बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन का महाअभियान है
- आदिवासी क्षेत्रों में साइंस, इंजीनियरिंग तथा मेडिकल शिक्षा के अवसर उपलब्ध हुए हैं
- खेल-कूद क्षेत्र में भी आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण, संसाधन तथा पोषण की सुविधाएँ दी गई हैं

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आदिजाति क्षेत्रों से निरक्षरता का कलंक मिटाने के लिए शुरू कराया गया शाला प्रवेशोत्सव आज शिक्षा क्षेत्र में विकास का वटवृक्ष बन गया है।

उन्होंने जोड़ा कि आदिजाति क्षेत्रों में वर्षों पुरानी शिक्षा की भूख अब पूरी हुई है और पूर्व के शाला प्रवेशोत्सवों में विद्यालयों में प्रविष्ट हुए बच्चों ने आज डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जैसे क्षेत्रों में समाज का नाम उज्ज्वल किया है।

मुख्यमंत्री 24वें शाला प्रवेशोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को दाहोद जिले की शालाओं में आयोजित प्रवेशोत्सव में सहभागी हुए। उन्होंने मोटी खरज, राहडुंगरी और गांगरडा गाँवों के विद्यालयों में कुल 300 से अधिक बच्चों का शाला प्रवेश कराया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने आधुनिक सुविधाओं तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से विद्यार्थियों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, कम्प्यूटर लैब, इंटरनेट सुविधा और आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इन सुविधाओं के कारण ग्रामीण एवं दूरदराजी क्षेत्रों के विद्यार्थी भी आधुनिक शिक्षा से जुड़कर प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न अभियानों तथा योजनाओं के परिणामस्वरूप आज अनेक विद्यार्थियों ने सफलता के नए शिखर पार किए हैं।

शिक्षा बीच में छोड़ देने वाले बच्चों को पुनः शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों का विवरण देते हुए श्री पटेल ने कहा कि अधिकारियों तथा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा ऐसे बच्चों के घर जाकर उनकी समस्याएँ जानकर और उन्हें फिर से स्कूल में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए सक्रिय भागीदार बनने तथा नियमित रूप से विद्यालय जाकर शिक्षकों के साथ बच्चों की प्रगति पर चर्चा करने का अनुरोध किया।

उचित मार्गदर्शन तथा अवसर मिले, तो बेटियाँ भी प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती हैं; इसका उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खरज गाँव की तीन बेटियों ने रग्बी खेल में राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचकर समग्र गाँव तथा गुजरात का गौरव बढ़ाया है।

विज्ञान सहित उच्च शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति योजना का आदिजाति विद्यार्थियों को अधिक लाभ पहुँचाने के लिए आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी है। इसके अतिरिक्त; नमो लक्ष्मी योजना में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बेटियों को कुल 50,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है तथा नमो सरस्वती योजना में कक्षा 11-12 में विज्ञान प्रवाह में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 50,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है।

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं; कक्षा 11-12 विज्ञान प्रवाह की पढ़ाई पूर्ण करने वाली बेटियों को विभिन्न योजनाओं के लाभों से कुल 75,000 रुपए तक की सहायता मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि पहले विज्ञान प्रवाह (साइंस स्ट्रीम) शिक्षा की सुविधाओं का अभाव था, परंतु अब जिला स्तर पर इंजीनियरिंग एवं मेडिकल जैसे उच्च शिक्षा संस्थान उपलब्ध होने से आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थी डॉक्टर तथा इंजीनियर बनने के सपने साकार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करने की आवश्यकता के बारे में बच्चों से कहा कि विद्यार्थियों को मोबाइल एवं टीवी का उचित उपयोग कर अध्ययन, पठन तथा शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समय निकालना चाहिए। अभिभावकों को भी बच्चों के टेक्नोलॉजी उपयोग पर सकारात्मक निगरानी रखते हुए उन्हें उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पर्यावरण तथा जल संरक्षण के लिए 'कैच द रेन' अभियान अंतर्गत वर्षा जल संग्रह तथा भूमिगत जल स्तर बढ़ाने और 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसे वृक्षारोपण अभियान द्वारा ग्रीन कवर बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी का आह्वान किया।

इस अवसर पर सांसद श्री जसवंतसिंह भाभोर ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान के कारण उमरगाम से अंबाजी तक के समग्र आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ऊँचा आया है तथा 'ड्रॉप-आउट रेशियो' में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा के प्रति व्याप्त उदासीनता अब दूर हुई है और आज आदिवासी युवा डॉक्टर, इंजीनियर एवं वकील बनकर समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। श्री भाभोर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में आज दाहोद जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी गुणवत्तायुक्त शिक्षा पहुँची है। उन्होंने गौरवपूर्वक कहा कि सिंगवड में 23 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अंग्रेजी माध्यम का आधुनिक विद्यालय इस क्षेत्र के बच्चों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करेगा।

सांसद ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 'वनबंधु कल्याण योजना-2' द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के विकास को नई गति दी है। उन्होंने सहर्ष कहा कि पूर्व में मजदूरी के लिए पलायन होता था, जिसे रोकने के लिए सरकार दृढ़ है। इसके अंतर्गत बारिया, धानपुर, गरबाडा, दाहोद और झालोद क्षेत्रों तक नर्मदा का जल पहुँचाने के लिए 5000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है, जो इस क्षेत्र में सिंचाई क्रांति लाएगी। उन्होंने सहर्ष कहा कि सिंचाई एवं शिक्षा क्षेत्र में इस क्रांति से आदिवासी परिवारों का पलायन रुकेगा और नई पीढ़ी आत्मनिर्भर बनेगी।

मुख्यमंत्री ने शाला में उपस्थित अभिभावक समिति के सदस्यों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर संवाद किया। इस आत्मीय संवाद के दौरान उन्होंने अभिभावकों के मूल्यवान सुझावों और अपेक्षाओं को जाना। बच्चों के उज्ज्वल शैक्षणिक भविष्य के निर्माण और गुणवत्तायुक्त शिक्षा के विस्तार के संबंध में उन्होंने अभिभावकों के साथ महत्वपूर्ण परामर्श कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पर्यावरण जतन का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने शाला प्रांगण में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया।

इस कार्यक्रम में विधायक श्री महेन्द्रभाई भाभोर, दाहोद जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती गमाबेन मोहनिया, संगठन के जिला अध्यक्ष श्री स्नेहलभाई धरिया, जिला कलेक्टर श्री सुरभि गौतम, जिला विकास अधिकारी श्री स्मिता लोढा सहित उच्चाधिकारी, संबंधित गाँवों के सरपंच, पदाधिकारी, शिक्षक, शाला के बच्चे और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त यात्री भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09079 मुंबई सेंट्रल–इंदौर स्पेशल को 28 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09080 इंदौर–मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 29 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
2. ट्रेन संख्या 09025 वलसाड–दानापुर स्पेशल को 27 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09026 दानापुर–वलसाड स्पेशल को 28 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
3. ट्रेन संख्या 09151 उधना–मधुबनी स्पेशल को 31 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09152 मधुबनी–उधना स्पेशल को 2 अगस्त, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
4. ट्रेन संख्या 09031 उधना–हसनपुर स्पेशल को 26 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09032 हसनपुर–उधना स्पेशल को 28 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
5. ट्रेन संख्या 09119 प्रतापनगर–लालकुआँ स्पेशल को 26 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09120 लालकुआँ–प्रतापनगर स्पेशल को 27 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
6. ट्रेन संख्या 09343 डॉ. अंबेडकर नगर–पटना स्पेशल को 30 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09344 पटना–डॉ. अंबेडकर नगर स्पेशल को 31 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
7. ट्रेन संख्या 09309 इंदौर–हज़रत निज़ामुद्दीन स्पेशल को 31 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09310 हज़रत निज़ामुद्दीन–इंदौर स्पेशल को 1 अगस्त, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
8. ट्रेन संख्या 09523 ओखा–शकूरबस्ती स्पेशल को 28 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09524 शकूरबस्ती–ओखा स्पेशल को 29 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
9. ट्रेन संख्या 09257 भावनगर टर्मिनस–शकूरबस्ती स्पेशल को 31 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09258 शकूरबस्ती–भावनगर टर्मिनस स्पेशल को 1 अगस्त, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09079, 09080, 09025, 09151, 09031, 09119, 09343, 09309, 09523 तथा 09257 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 25.06.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं रेक संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सुमुल डेयरी चुनाव में भाजपा की मजबूत शुरुआत, पांच उम्मीदवार निर्विरोध विजयी; 11 सीटों पर अब होगा सीधा मुकाबला

सूरत। दक्षिण गुजरात की सहकारिता राजनीति में अहम माने जाने वाले सुमुल डेयरी प्रबंधन समिति चुनाव 2026 ने अब पूरी तरह राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में अपने सभी अधिकृत उम्मीदवार उतारकर जहां संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया है, वहीं पांच सीटों पर उसके उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचित होना पार्टी के लिए बड़ी शुरुआती सफलता माना जा रहा है। अब शेष 11 सीटों पर होने वाले मुकाबले पर पूरे सहकारी क्षेत्र और राजनीतिक हलकों की नजरें टिक गई हैं।

सूरत और तापी जिलों के दुग्ध उत्पादक किसानों से सीधे जुड़े इस चुनाव को केवल एक सहकारी संस्था का चुनाव नहीं माना जाता, बल्कि इसे दक्षिण गुजरात की सहकारिता और ग्रामीण राजनीति का महत्वपूर्ण शक्ति परीक्षण भी समझा जाता है। यही कारण है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों और विभिन्न गुटों की गतिविधियां लगातार तेज बनी रहीं।

सुमुल डेयरी की प्रबंधन समिति के लिए कुल 16 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें सूरत जिले की नौ और तापी जिले की सात सीटें शामिल हैं। नामांकन की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पांच सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के सामने कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं उतरा। परिणामस्वरूप इन सीटों पर चुनाव की आवश्यकता नहीं रही और उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया।

निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों में चोर्यासी सीट से संदीप देसाई, कामरेज सीट से बलवंत पटेल, मांगरोल सीट से राजू पाठक, बारडोली सीट से अजीतभाई पटेल तथा पलसाना सीट से भरतसिंह सोलंकी शामिल हैं। इन उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत को भाजपा की संगठनात्मक पकड़ और स्थानीय स्तर पर मजबूत नेटवर्क का परिणाम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही पांच सीटों पर जीत दर्ज कर लेना भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त साबित हो सकता है।

नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सूरत सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जिला भाजपा अध्यक्ष भरतभाई राठौड़, विधायक संदीप देसाई, राजू पाठक तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी स्थिति की जानकारी दी। इस दौरान नेताओं ने इसे संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि शेष 11 सीटों पर भी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

भरतभाई राठौड़ ने कहा कि पांच उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि डेयरी क्षेत्र में भाजपा समर्थित नेतृत्व के प्रति किसानों और सहकारी संस्थाओं का भरोसा मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सुमुल डेयरी केवल एक डेयरी संस्था नहीं बल्कि लाखों दुग्ध उत्पादक किसानों की आर्थिक रीढ़ है और इसके प्रबंधन में सक्षम एवं अनुभवी नेतृत्व की आवश्यकता है।

हालांकि चुनावी प्रक्रिया के दौरान पार्टी को कुछ आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से वालोड और ओलपाड सीटों पर बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी ने राजनीतिक चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है। भाजपा नेतृत्व द्वारा अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए जाने के बावजूद कुछ नेताओं ने स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिससे संगठन के भीतर असंतोष की झलक भी दिखाई दी है।

वालोड सीट से नरेश पटेल और ओलपाड सीट से वसंतभाई पटेल ने पार्टी की आधिकारिक घोषणा के बावजूद अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। इस घटनाक्रम ने भाजपा नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि सहकारी चुनावों में स्थानीय समीकरण कई बार अप्रत्याशित परिणाम भी दे सकते हैं।

इस मुद्दे पर भरतभाई राठौड़ ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि दोनों नेताओं को पार्टी द्वारा अधिकृत उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। इसके बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता दोनों से बातचीत करेंगे और उन्हें संगठन के हित में नामांकन वापस लेने के लिए समझाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा अनुशासित संगठन है और संगठनात्मक निर्णयों का पालन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की जिम्मेदारी है। यदि बातचीत के बाद भी संबंधित उम्मीदवार चुनाव मैदान में बने रहते हैं तो पार्टी अनुशासन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी स्थिति में निलंबन या निष्कासन जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव अक्सर स्थानीय स्तर पर शक्ति संतुलन का संकेत देते हैं। सुमुल डेयरी जैसी बड़ी संस्था का चुनाव विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसका सीधा संबंध हजारों दुग्ध उत्पादक समितियों और लाखों किसानों से है। डेयरी प्रबंधन समिति में चुने जाने वाले सदस्य संस्था की नीतियों, विकास योजनाओं और आर्थिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

दक्षिण गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी आंदोलन ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में सुमुल डेयरी का नेतृत्व किसके हाथ में होगा, यह केवल सहकारिता क्षेत्र का प्रश्न नहीं बल्कि क्षेत्रीय विकास और किसान हितों से भी जुड़ा हुआ विषय माना जाता है।

पांच सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब सभी की नजरें शेष 11 सीटों पर होने वाले चुनावी मुकाबलों पर टिकी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय समीकरण, सहकारी संस्थाओं का समर्थन और किसानों के बीच प्रभाव रखने वाले नेताओं की भूमिका चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि आगामी दिनों में चुनाव प्रचार और राजनीतिक गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है।

सुमुल डेयरी चुनाव 2026 अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां भाजपा ने शुरुआती बढ़त तो हासिल कर ली है, लेकिन अंतिम तस्वीर शेष 11 सीटों के परिणाम तय करेंगे। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह चुनाव दक्षिण गुजरात की सहकारिता राजनीति का भविष्य तय करने के साथ-साथ विभिन्न संगठनों और नेताओं की वास्तविक ताकत का भी परीक्षण साबित होगा। फिलहाल निर्विरोध जीत के साथ भाजपा उत्साहित दिखाई दे रही है, जबकि विपक्ष और बागी उम्मीदवार आने वाले मुकाबलों को रोचक बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं।

मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने राज्य के पर्यटन एवं तीर्थस्थलों के कायाकल्प के उद्देश्य से उप विभिन्न विकास कार्यों को दी स्वीकृति

- राज्य में पर्यटकों की सुविधा और आस्था के केंद्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
- विभिन्न तीर्थस्थलों और पर्यटन स्थलों पर आधुनिक ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएंगी
- उप मुख्यमंत्री द्वारा तीर्थस्थलों और पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों के लिए 3.28 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई

गांधीनगर : गुजरात को वैश्विक पर्यटन नक्शे पर और अधिक सशक्त बनाने तथा राज्य के पवित्र तीर्थस्थलों पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने बुधवार को राज्य के पर्यटन एवं तीर्थस्थलों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

गुजरात प्रकृति, संस्कृति एवं आस्था का अद्भुत संगम है। राज्य के विकास मॉडल में पर्यटन उद्योग और तीर्थस्थलों का विकास सरकार की प्राथमिकताओं रही है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध हों, इस उद्देश्य से विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं और आस्था केंद्रों के विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

वलसाड जिले के कोसंबा स्थित श्री अक्षरपुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर में सुविधाओं के विस्तार के लिए तथा डांग जिले के सापुतारा पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख केंद्र सनराइज एवं सनसेट पॉइंट तक जाने वाले मार्ग के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त; राकोट में उपलेटा स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहन देने के लिए सोलर रूफटॉप परियोजना को स्वीकृति दी गई है। वहीं, अहमदाबाद जिले के भोयणी स्थित श्री मल्लीनाथजी महाराज ऐतिहासिक जैन तीर्थ में यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी व्यय स्वीकृत किया गया है।

वडोदरा जिले में श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर के प्राचीन मंदिर के मुख्य जीर्णोद्धार, बोरवेल, कोटा स्टोन फ्लोरिंग, सजावटी द्वार तथा विद्युतीकरण सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिए भी अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार; सूरत में अडाजण स्थित श्री हाटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सिविल एवं सोलर से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन सभी तीर्थस्थलों और पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री द्वारा 3.28 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है।

उप मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए हैं कि सभी स्वीकृत परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर तथा उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण की जाएं। सरकार के इस निर्णय से आने वाले समय में गुजरात के पर्यटन एवं तीर्थस्थल क्षेत्र को नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी।

बाइक सवार 107 लंबित चालानों और 2.36 लाख रुपये के जुर्माने के साथ पकड़ा गया, पुलिस ने बाइक जब्त की

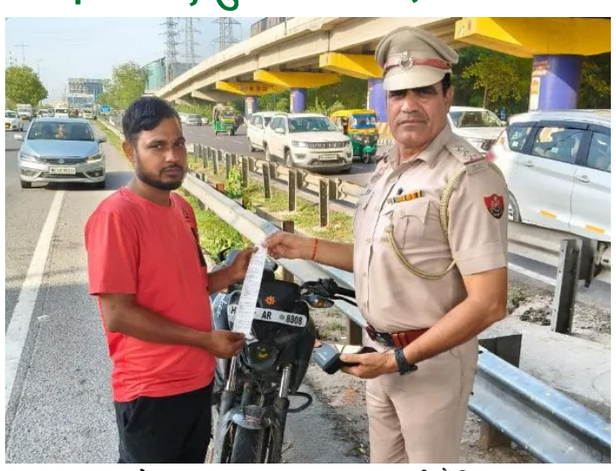

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश में कई बेहतर मॉडल मौजूद हैं, जिनमें से इस एक मॉडल की बाइक पर कुल 107 चालान लंबित हैं, जिनका जुर्माना 23 लाख रुपये है। ऐसा मामला दिल्ली के पास गुड़गांव के एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखा।

नियमित वाहन निरीक्षण के दौरान, यातायात पुलिस ने एक युवक को उसकी बाइक के साथ रोका। उसने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए पुलिस ने उसे रोक लिया। आमतौर पर, सड़क पर तैनात यातायात पुलिस दो विकल्प देती है: पहला, हाल ही में किए गए अपराध का जुर्माना भरकर चले जाना; दूसरा, क्या हम अभी चालान जारी कर दें और आप बाद में यातायात पुलिस के पास जाकर जुर्माना भर दें?

इस बाइकर ने "अभी चालान बनवाएं, जुर्माना बाद में भरें" का विकल्प चुना। हालांकि, जब उसने वेबसाइट पर अपनी बाइक का नंबर चेक किया, तो उसे पता चला कि इस बाइक पर पहले से ही 107 चालान लंबित हैं, जिनका कुल जुर्माना 23 लाख रुपये से अधिक है। यह रकम देखकर पुलिस ने उसकी बाइक जब्त कर ली।

लखनऊ में आग लगने की घटना में 15 लोगों की मौत के बाद कार्रवाई तेज की गई, अग्नि सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सोमवार को लखनऊ में जिस इमारत में आग लगी, वह एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में चल रही थी, जिसमें पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय, आपातकालीन निकास या धुआं निकालने की व्यवस्था नहीं थी। अलीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, इमारत का नक्शा आवासीय भवन के रूप में दिखाया गया था। पुलिस द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में यह जानकारी दी गई है। इमारत में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थीं, और इमारत के मालिक, एक पालतू जानवरों की दुकान और एक एनिमेशन सेंटर के संचालकों सहित चार लोगों के नाम दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या का प्रयास, लापरवाही या गैरजिम्मेदाराना कृत्य जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ जाए, और उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर के अनुसार, 22 जून को दोपहर लगभग 2:30 बजे अलीगंज के सेक्टर डी स्थित एक तीन मंजिला इमारत में पालतू जानवरों की दुकान और क्लिनिक में आग लग गई। दुकान और क्लिनिक भूतल और पहली मंजिल पर थे, दूसरी मंजिल पर वीडियो गेमिंग जोन और 3डी एनिमेशन सेंटर तथा तीसरी मंजिल पर आईटी नेटवर्किंग कार्यालय था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इमारत के मालिकों और व्यवसायों से जुड़े लोगों ने "अग्नि सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी और न ही आपातकालीन निकास या प्रवेश द्वार की कोई व्यवस्था थी। प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही मुख्य मार्ग था और कोई अन्य निकास द्वार या आपातकालीन द्वार नहीं था।" इस आग में पंद्रह लोगों की मौत हो गई। इनमें से अधिकांश छात्र थे जिनकी मृत्यु दम घुटने और जलने से हुई।

जबकि 9 अन्य घायल हो गए, जिन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया।

पुलिस के अनुसार, अब तक पालतू जानवरों की दुकान के प्रबंधक रामकृष्ण उपाध्याय (43), मकान मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (62), एनिमेशन सेंटर के प्रबंधक तुषार कृष्ण जायसवाल (31) और सुरेश कुमार शाहू को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी पैनल के सदस्य एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने पत्रकारों को बताया कि एसआईटी सात दिनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।